भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2688

दिनांक 4 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

मुक्त व्यापार समझौते और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

2688 श्री यूसुफ पठान:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में संपन्न मुक्त व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन तथा वर्तमान में जारी व्यापार वार्ताओं की स्थिति क्या है;

(ख) इन समझौतों के भारत के निर्यात, विनिर्माण क्षेत्र तथा रोजगार पर संभावित प्रभाव क्या हैं;

(ग) भारतीय निर्यातकों, विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त समझौतों से क्षेत्र-वार निर्यात वृद्धि के अनुमान क्या हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) हाल ही में संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और चल रही व्यापार वार्ताओं के कार्यान्वयन की स्थिति अनुलग्नक में दी गई है।

(ख) एफटीए आर्थिक साधन हैं जिनका उद्देश्य व्यापार का विस्तार करना, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना और आर्थिक एकीकरण को मजबूत करना है। एफटीए लागू होने (ईआईएफ) टैरिफ उन्मूलन, चरणबद्ध टैरिफ कटौती/उन्मूलन और विभिन्न क्षेत्रों में संवेदनशील/अपवर्जन सूचियों के माध्यम से संतुलित बाजार पहुंच प्रदान करते हैं। कार्यान्वित एफटीए में शामिल क्षेत्रों, टैरिफ संरचना और प्रमुख विशेषताओं का विवरण **https://www.commerce.gov.in/#/ international-trade/trade-agreements** पर उपलब्ध है।

मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के प्रभाव का आकलन एक निरतंर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, यूके और न्यूजीलैंड के साथ भारत के हाल ही में संपन्न मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से घरेलू उद्योगों के संवर्धित व्यापार और विकास के अवसर प्रदान होने की प्रत्याक्षा है। समझौतों में निवेश और बाजार पहुंच से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जिससे घरेलू उत्पादन को सहयोग मिलने, निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और विनिर्माण, कृषि, एमएसएमई और संबद्ध क्षेत्रों सहित श्रम गहन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होने की प्रत्याक्षा है।

इसके अतिरिक्त, नई एफटीए वार्ताएं शुरु करने से पहले, सरकार यह सुनिश्चित करती है कि वार्ताओं के सभी चरणों में क्षेत्र-विशिष्ट हितधारकों के साथ परामर्श किया जाए। व्यापक, संतुलित, निष्पक्ष और पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणाम प्राप्त करने के प्रयास से एफटीए पर वार्ता की जाती है। यह व्यापारिक साझेदार देशों में भारतीय निर्यातकों के लिए एक अधिमान्य, स्थिर और पूर्वानुमानित व्यापार इकोसिस्टम को भी सक्षम बनाता है। इस संरचित दृष्टिकोण के अतिरिक्त, कार्यान्वयन के बाद, सरकार व्यापार संवर्धन, व्यापार सुविधा और यदि कोई चुनौतियां हों तो उनके समाधान के माध्यम से प्रभावी एफटीए उपयोग सुनिश्चित

करने के लिए सभी हितधारकों के साथ निरंतर संपर्क में रहती है। घरेलू प्राथमिकताओं की रक्षा करते हुए निर्यात वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों के लिए कार्यनीतिक सुरक्षा उपाय मौजूद हैं।

(ग) सरकार ने समय-समय पर घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने और एमएसएमई, छोटे निर्यातकों तथा क्षेत्रीय उद्योगों सहित देश से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल और उपाय किए हैं, जो कि निम्नवत हैं:

(i) दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी विदेश व्यापार नीति, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक बाजार में अधिक प्रभावी ढंग से एकीकृत करना, व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना और देश को एक विश्वसनीय एवं भरोसेमंद व्यापार साझेदार के रूप में स्थापित करना है;

(ii) निर्यात संवर्धन मिशन: सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से एमएसएमई के लिए भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना है। ईपीएम दो एकीकृत उप-योजनाओं के माध्यम से संचालित होगा:

- निर्यात प्रोत्साहन, जिसका उद्देश्य ब्याज अनुदान, निर्यात फैक्टरिंग, निर्यात ऋण के लिए संपार्श्विक गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी और ऋण वृद्धि सहायता जैसे साधनों के माध्यम से व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार करना है; और
- निर्यात दिशा, जो कि निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग और पैकेजिंग, बाजार पहुंच पहल, निर्यात लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग, और व्यापार आसूचना जैसे अन्य व्यापार सहायकों पर केंद्रित है।

(iii) भारत ट्रेड नेट (बीटीएन): केंद्रीय बजट 2025 में घोषित भारत ट्रेड नेट (बीटीएन) एक प्रमुख डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पहल है जो सरल, कागज रहित दस्तावेज़ीकरण को सक्षम करके, अनुपालन बोझ को कम करके और वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त त्वरित, सुरक्षित व्यापार लेनदेन को सुविधाजनक बनाकर एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती है।

(iv) जिला निर्यात केंद्र (डीईएच) और ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र जैसे जमीनी स्तर के कार्यक्रमों की शुरुआत से एमएसएमई, स्टार्ट-अप्स और कारीगरों को कम लागत और सरलीकृत निर्यात प्रक्रियाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने में मदद मिलती है।

(v) राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और पीएम गति शक्ति के माध्यम से अवसंरचना को मजबूत करने से बहुआयामी कनेक्टिविटी बढ़ती है और लॉजिस्टिक्स लागत कम होती है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं को कम करके एमएसएमई निर्यातकों को सीधे लाभ होता है।

(vi) व्यापार को सुगम बनाने और निर्यातकों द्वारा एफटीए के उपयोग को बढ़ाने के लिए मूल प्रमाण पत्र हेतु एक सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है।

(vii) सरकार व्यापार संवर्धन, व्यापार सुविधा और आयात एवं निर्यात से संबंधित उपचारात्मक उपायों के माध्यम से व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए विदेशों में भारतीय मिशन, निर्यात संवर्धन परिषदें उद्योग संघों और संबंधित मंत्रालयों/विभागों सहित व्यापार संघों और संबंधित हितधारकों के साथ निरंतर संपर्क में रहती है।

(viii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने देश भर में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में 65 निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसी) स्थापित किए हैं ताकि एमएसएमई को उनके उत्पादों और सेवाओं के निर्यात में आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जा सके। इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) योजना एमएसएमई को विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों/क्रेता-विक्रेता बैठकों में भाग लेने में सुविधा प्रदान करती है।

(घ) मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के संचालन ने अभूतपूर्व बाजार पहुंच प्रदान करके, व्यापार बाधाओं को कम करके, आपूर्ति श्रृंखला लिंकेज को बढ़ाकर और सभी क्षेत्रों में भारतीय निर्यातकों के लिए नए अवसर पैदा करके प्रमुख भागीदार देशों के साथ भारत के व्यापार संबंधों को मजबूत किया है। भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों सहित लगातार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारत का निर्यात वित्त वर्ष 2022-23 में 776.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 863.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वित्त वर्ष 2025-26 में प्रमुख एफटीए भागीदार देशों और व्यापार ब्लॉकों को व्यापारिक निर्यात 179.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है, जो भारत के कुल व्यापारिक निर्यात का 40.5 प्रतिशत है। हाल के एफटीए भागीदारों को व्यापारिक निर्यात ने भी महत्वपूर्ण निर्यात वृद्धि का संकेत दिया है। उदाहरण के लिए, संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (सीईपीए कार्यान्वयन से पहले) से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 37.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि ईसीटीए के कार्यान्वयन के बाद ऑस्ट्रेलिया को निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में 4.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 7.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इसी तरह, ईएफटीए देशों को निर्यात वित्त वर्ष 2019-20 में 1.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 1.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

इसके अलावा, निर्यात और आयात सहित व्यापार के रुझान कई वैश्विक और घरेलू कारकों से प्रभावित होते है जिनमें आर्थिक विकास, भू-राजनीतिक विकास, उद्योग की मांग, घरेलू जरूरतें, वस्तु मूल्य उतार-चढ़ाव और उभरती आपूर्ति श्रृंखलाएं शामिल हैं।

*****

दिनांक 04.08.2026 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2688 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

हाल के मुक्त व्यापार समझौते

क्र. सं.	समझौते का नाम	समझौते पर हस्ताक्षर की तिथि	समझौता कार्यान्वित होने की तिथि
1	भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (सीईसीपीए)	22 फरवरी, 2021	1 अप्रैल, 2021
2	भारत-यूएई सीईपीए	18 फरवरी, 2022	1 मई, 2022
3	भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता (भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए)	2 अप्रैल, 2022	29 दिसंबर, 2022
4	भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए) (आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड)	10 मार्च, 2024	01 अक्टूबर, 2025
5	भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए)	24 जुलाई, 2025	15 जुलाई, 2026
6	भारत - ओमान सीईपीए	18 दिसंबर, 2025	01 जून, 2026
7	भारत-न्यूज़ीलैंड एफटीए	27 अप्रैल, 2026	अनुसमर्थन प्रक्रिया के अधीन

नोट: भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की वार्ता दिनांक 27 जनवरी, 2026 को संपन्न हुई। साथ ही, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिनांक 7 फरवरी, 2026 को घोषित किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत पारस्परिक और आपसी रूप से लाभकारी व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते के फ्रेमवर्क पर सहमत हो गए हैं। वार्ता जारी है।

चल रही एफटीए वार्ताएं

चल रही एफटीए वार्ताएं

1. भारत-चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए)
2. भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए)
3. भारत-यूरेशियन आर्थिक संघ (भारत-ईएईयू) एफटीए
4. भारत-इजराइल एफटीए
5. भारत-पेरू एफटीए
6. भारत-यूएसए द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए)
7. भारत-मालदीव एफटीए

समीक्षा/ उन्नयन वार्ता के अधीन एफटीए

1. भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) की समीक्षा
2. आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की समीक्षा
3. भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए)
4. भारत-श्रीलंका आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता (ईटीसीए)

*****